



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 12 मार्च, 2007/21 फाल्गुन, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 12 मार्च, 2007

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-14/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकार (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक

12 मार्च, 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2007

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम,
2003 (2003 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, संक्षिप्त नाम।
भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2007 है।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) धारा 2 का
2003 का 13 अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा संशोधन।
2 के खण्ड (क) में "हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों को 31 जुलाई, 2006 को
अनुज्ञेय भत्ते अभिप्रेत हैं" शब्दों, अंकों और चिन्ह के स्थान पर " वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में "नियम बना सकेगी" शब्दों धारा 4 का
से पूर्व "भूतलक्षी प्रभाव से" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

३१

राज्य विधान मण्डल ने वर्ष, 2003 में राज्य में न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया था। राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए न्यायिक अधिकारी सेवा नियम, 2004 अधिसूचित किए थे।

तथापि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 06-12-2005 द्वारा, 2002 (4) एस.सी.सी. 247 के रूप में संप्रकाशित निर्णय के निबन्धनों के अनुसार अन्य बातों के साथ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय-XIX में वर्णित समस्त भत्ते और प्रसुविधाएं 11-11-1999 से देने के लिए निदेश पारित किए। तत्पश्चात् अपने तारीख 07-02-2006 के आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट के उपर्युक्त अध्याय-XIX में अंकित विभिन्न भत्तों, सुख-सुविधाओं और अग्रिमों का उल्लेख किया तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निदेशों की दो मास के भीतर अनुपालना करने के निर्देश दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित उपर्युक्त निदेशों के दृष्टिगत, शेट्टी आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में मामले पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और राज्य सरकार ने कतिपय भत्तों की बाबत तारीख 17-07-2006 को एक अधिसूचना जारी की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः अपने आदेश तारीख 21-11-2006 द्वारा राज्य सरकार को भत्तों/सुख सुविधाओं की बाबत पांच विशिष्ट सिफारिशों के विषय में अननुपालन के पहलूओं को जांचने के निदेश दिए और छह सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दाखिल करने के निदेश दिए।

राज्य विधायिका ने भारत के संविधान के अधीन अपनी विधायी शक्ति के अन्तर्गत पहले ही हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2003 अधिनियमित कर दिया था और राज्य सरकार उक्त अधिनियमिति को प्रवर्तित करने के लिए विधितः आबद्ध है। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी सेवा नियम, 2004 के नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 17-07-2006 को एक अधिसूचना जारी की गई थी तथा उसमें विहित से भिन्न भत्ते और प्रसुविधाएं प्रदान करना वर्ष, 2006 में यथा संशोधित पूर्वोक्त अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों के अल्पीकरण में होगा। चूंकि वह संशोधन "भत्तों" को उन भत्तों के रूप में परिभाषित करता है जो 31 जुलाई, 2006 को न्यायिक अधिकारियों को अनुज्ञेय थे। तदनुसार, तारीख 21-11-2006 के आदेशों के उपान्तरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में, उपरोक्त तथ्यों और विधिक स्थिति से अवगत कराने (मूल्यांकन) के लिए आवेदन किया गया था। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के मत को उचित नहीं समझा और उक्त आवेदन को, पूर्णतः भ्रमित और न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग करार देते हुए खारिज कर दिया।

तारीख 21-11-2006 के पूर्व आदेश के निबन्धनों के अनुसार शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए तारीख 10-01-2007 के निदेशों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2003 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया ताकि राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को भूतलक्षी प्रभाव से विनियमित करने के लिए नियम बना सके और पद "भत्ते" को पुनः परिभाषित कर सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

तारीख:.....2007.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें विनियमित करने हेतु भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन
विधेयक, 2007

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) का
और संशोधन करने के लिए विधेयक।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

जे० एन० बारोवालिया,
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : 2007.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2007.

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2007

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Amendment Act, 2007. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in clause (a), for the words, figures and signs “admissible to the Judicial Officers in Himachal Pradesh on 31st July, 2006”, the words “as may be notified by the State Government from time to time” shall be substituted. Amendment of section 2.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “make rules”, the words “with retrospective effect” shall be inserted. Amendment of section 4.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Legislature in the year, 2003 had enacted the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Condition of Services) Act, 2003 to provide for regulation of the Pay, Allowances and Conditions of Services of the Judicial Officers in the State. The State Government further in exercise of the powers conferred by articles 233, 234 and proviso to article 309 of the Constitution of India read with sub-section (1) of section 4 of the Act *ibid* had notified the Judicial Officers Services Rules, 2004 for regulating the recruitment and conditions of service of the Judicial Officers.

However, the Hon'ble Supreme Court of India *vide* its order dated 6-12-2005 passed directions *inter alia* to the States/Union Territories to release all the allowances and benefits enumerated in Chapter-XIX of Shetty Commission Report w.e.f. 11-11-1999 in terms of the Judgment reported as 2002 (4) S.C.C. 247. Subsequently in its order dated 7-02-2006, the Supreme Court mentioned the various allowances, amenities and advances figuring in aforesaid Chapter-XIX of the report and various States/Union Territories were directed to comply with the directions within two months. In view of the aforesaid directions passed by the Hon'ble Supreme Court from time to time, the matter in relation to recommendations of Shetty Commission was duly considered and the State Government issued a notification dated 17-07-2006 in respect of certain allowances. The Hon'ble Supreme Court again *vide* its order dated 21-11-2006 directed the State Government to look into the aspects of non-compliance regarding five specific recommendations qua the allowances/amenities and file the affidavit within six weeks.

The State Legislature within the realm of its legislative power under the Constitution of India had already enacted the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 and the State Government is legally bound to enforce the said enactment. In exercise of powers conferred by rule 7 of the Himachal Pradesh Judicial Services Rules, 2004, a notification dated 17-07-2006 had been issued, and the grant of allowances and benefits other than those prescribed therein would be in derogation to the express provisions of the Act *ibid* as amended in the year 2006. Since that amendment defines 'allowances' as those allowances that were admissible to Judicial Officers as on 31st July, 2006. Accordingly, an application for modification of the orders dated 21-11-2006 was preferred in the Hon'ble Supreme Court, appraising it of the aforesaid facts and legal position. However, the apex Court did not appreciate the contention of the State Government and dismissed the said application terming it as an abuse of the process of the Court and being wholly misconceived.

As a consequence of the directions dated 10-01-2007 directing the filing of an affidavit in terms of the previous order dated 21-11-2006, it has been decided to suitably amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 in order to empower the State Government to make rules with retrospective effect regulating Pay, Allowances and Conditions of Service of the Judicial Officers and to redefine the expression "Allowances".

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla:

The.....2007.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules regulating pay, allowances and conditions of service of the Judicial Officers with retrospective effect. This delegation is essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND
CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2007**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions
of Service) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003).*

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. N. BAROWALIA,
Secretary (Law).

Shimla:

The..... 2007.